हस्तिनापुर, तराई तथा पीलीभीत (उत्तर प्रदेश) में लघु तथा कुटीर उद्योग

4432. **डा० कैलाश प्रकाश** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या यह सच है कि देश के विभाजन के बाद विस्थापितों को हस्तिनापुर जिला मेरठ तथा बरेली पीलीभीत तथा नैनीताल (उत्तर प्रदेश) के तराई क्षेत्र में बसाया गया था और यह आश्वासन दिया गया था कि उन्हें पूरी तरह से बसाने के लिये लघु तथा कुटीर उद्योगों की स्थापना की जायेगी और यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम किंकर) : भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों को ऋण देकर मेरठ जिले में हस्तिनापुर और बरेली, पीलीभीत और नैनीताल के तराई क्षेत्र में कृषि भूमि और व्यापार व्यवसाय तथा उद्योग में बसाया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार ये सभी विस्थापित व्यक्ति बहुत पहले बसा दिए गए हैं।

भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए नए प्रवासियों को बरेली, पीलीभीत और नैनीताल के जिलों में कृषि में बसाया गया है। हस्तिनापुर में नए प्रवासियों और प्रत्यावासियों को रोजगार/प्रशिक्षण देने के लिए सदन स्पीनिंग मिल्स के नाम से एक व्यापक उद्योग योजना लागू की गई है।

Fruit Processing Plant

4433. SHRI C. K. CHANDRAPPAN: SHRI AHMED HUSSAIN:

Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether Government have a proposal under consideration to set up a fruit processing plant in the country with the financial assistance of German Democratic Republic; and

(b) if so, details of the plant and the location selected for this purpose?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PARTAP SINGH): (a) and (b). The National Agricultural Cooperative Marketing Federation is considering the possibility of setting up a Fruit and Vegetable Processing Plant at Silcher in the North-Eastern Region. A Techno Economic feasibility report has been prepared jointly by the experts of GDR and NAFED which envisages processing of pine-apples, oranges and tomatoes. GDR is expected to provide financial asistsance in the term of loan to cover the cost of machinery imported from GDR or any other socialist country.

Memorandum from All India Central Ground Water Board Employees

4434. SHRIMATI PARVATHI KRISHNAN: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether Government have received any memorandum from All India Central Ground Water Board Employees Association, Faridabad;

(b) if so, what are their demands; and

(c) decision taken thereon?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a)